

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक : 12 जुलाई, 2016

विषय- मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में एक्वागार्ड लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1293/U.H.C.2016/Management, दिनांक 22.03.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में अधिवक्ताओं व वादकारियों की पेयजल व्यवस्था हेतु एक नया एक्वागार्ड लगाये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आयोजनेत्तर पक्ष में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से ₹ 47,600/- (₹ सैंतालिस हजार छः सौ मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका व मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा, साथ ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं उक्त के विषय में समर्थ-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग तथा पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, बजट मैनुअल/वित्तीय हस्त पुस्तिका, वित्तीय नियमों, निर्धारित प्रक्रिया एवं स्थापित व्यवस्था आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय की सूचना प्रमाण सहित शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जायेगा, स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- (4) उक्त मशीन के क्रय के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित सुसंगत नियमों का पालन किया जायेगा तथा क्रय की कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जायेगा।
- (5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आइडियल कैपेसिटी का आंकलन करने के उपरान्त ही मशीन का क्रय किया जाये ताकि सभी मशीन का ऑप्टीमम यूज हो सके।

(6) वित्तीय वर्ष के अंत तक यदि उक्त मशीन कय नहीं की जाती है या कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह शासन को दिनांक 31.03.2017 तक समर्पित कर दी जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-102-उच्च न्यायालय-03-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-490, दिनांक 31.03.2016 में निहित व्यवस्थानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( आलोक कुमार वर्मा )  
सचिव।

संख्या-101/(1)/XXXVI (3)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)  
अपर सचिव।